



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2009/ आश्विन 9, 1931

No. 309]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2009/ASVINA 9, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 14/08/2008-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

प्रक्रिया

क. 1 प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

क. दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 को निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने एक जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की और इसे भारत के राजपत्र में विधिवत ढंग से अधिसूचित किया तथा इसके द्वारा चीन जन. गण. और हांगकांग (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की थी ।

ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 17-2-2009 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और हितबद्ध पक्षकारों से इनके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था ।

ग. प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति भेजी थी, जिनसे उक्त जांच परिणामों के संबंध में पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर उनके विचारों, यदि कोई हों, से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ।

घ. प्राधिकारी ने दिनांक 18 मई, 2009 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों से प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त करने और उनका खंडन, यदि कोई हों, करने का अनुरोध किया गया था।

ङ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया था;

च. प्राधिकारकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को इन जांच परिणामों में समुचित रूप से स्थान दिया गया है;

छ. संबंधित नियम 16 के अनुसार, इन जांच परिणामों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधारों को 16 सितंबर, 2009 को सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और इनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में विधिवत ढंग से विचार किया गया है।

ज. इस अधिसूचना में \*\*\* चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को प्रदर्शित करता है;

झ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 (12 महीनों) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2004-मार्च, 2005, अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007 की अवधि और जांच अवधि शामिल है।

ञ. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के आयातकों/औद्योगिक प्रयोक्ताओं को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित जांच से संगत समझी जाने वाली सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था।

ट. प्राधिकारी ने इस स्तर पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यता के संबंध में आवश्यक सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया है।

## **ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

### **ख.1 घरेलू उद्योग के विचार**

2. विचाराधीन उत्पाद 30% फ्लैक्स मात्रा से अधिक की बुनी हुई फैब्रिक है। "फ्लैक्स" और लाइनेन पर्यायवाची हैं और "फ्लैक्स" शब्द को "लाइनेन" के नाम से भी जाना जाता है और इनका उपयोग फ्लैक्स फाइबर से बने यार्न या फैब्रिक के उत्पादन में किया जा सकता है। प्रायः इनका उपयोग बुने हुए बैड, बाथ, टेबल और रसोई के वस्त्रों के एक वर्ग का वर्णन करने के लिए भी समान रूप से होता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स का उपयोग तौलिया, चादरों आदि के लिए काफी अधिक होता है। पूर्व में यह शब्द हल्के वजन के अधो वस्त्रों जैसे शर्ट, कुर्तियों, वेस्ट शर्टों, लिंगरी और शर्ट की हटाने योग्य कॉलरों और कफों के लिए प्रयोग किया जाता था।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 53 में उपशीर्ष 5309 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं चीन और हांगकांग के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं। उपभोक्ताओं द्वारा भी आयातित उत्पाद को समान श्रेणी में उपयोग किया जाता है। इस उत्पाद में समान मूल तकनीकी विशेषताएं हैं और इसके कार्य और प्रयोग समान हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित फ्लैक्स फैब्रिक और भारत में आयातित संबद्ध फ्लैक्स फैब्रिक के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित फ्लैक्स फैब्रिक्स और भारत में आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

## **ख.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार:-**

8. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के बारे में कोई टिप्पणी या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

## **ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

9. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स हैं, जिन्हें सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। "फ्लैक्स" और "लाइनेन" पर्यायवाची हैं और फ्लैक्स शब्द को लाइनेन के रूप में भी जाना जाता है और इनका उपयोग फ्लैक्स फाइबर से बने यार्न और फैब्रिक के उत्पादन में किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रायः बुने हुए बिस्तर बाथ टब, मेज और किचन टेक्सटाइल के एक वर्ग का वर्णन करने के लिए समानार्थी शब्द के रूप में किया जाता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स का तौलियों और चादरों आदि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अध्याय 53 में उपशीर्ष 53.09 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

10. पाटनरोधी नियम के नियम 2 (घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि "समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 30% से अधिक फ्लैक्स की मात्रा वाले बुने हुए फैब्रिक का कोई खास उत्पादन नहीं कर रहा है। जांच अवधि के दौरान 30% से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाले बुने हुए फैब्रिक का उत्पादन कुल उत्पादन का केवल 0.62% था जो कोई खास उत्पादन नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग 50% से अधिक फ्लैक्स

मात्रा वाले बुने हुए फैब्रिक का प्रमुख रूप से उत्पादन कर रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित बुने हुए फैब्रिक (जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50% से अधिक है) में ऐसी विशेषताएं हैं जो संबद्ध देशों से आयातित फ्लैक्स फैब्रिक के समान हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयात की जा रही बुनी हुई फैब्रिक (50% से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाली) समान वस्तुएं हैं और ये इस जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ नियमों के अर्थ के भीतर विचाराधीन उत्पाद हैं।

## ग. घरेलू उद्योग

### ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. यह आवेदन मै. जयश्री टेक्सटाइल्स (आदित्य बिरला नूवो लि. की एक इकाई) इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है और 7 अन्य विनिर्माताओं ने इसका समर्थन किया है जो इस प्रकार हैं: (क) गोवर्धन ओवरसीज प्रा.लि. (ख) वीएमएम वीव्स इंडिया लि., (ग) वी एस पलानीस्वामी कं. (घ) वसंती फैब्रिक्स, (ङ) महेन्द्र टेक्सटाइल्स (च) मार्स एक्सपोर्ट, करूर, (छ) राम टेक्सटाइल्स, करूर। याचिकाकर्ता ने जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान चीन से फ्लैक्स फैब्रिक्स का आयात किया है तथापि, यह आयात कंपनी के उत्पादन (6.27%) और भारत में खपत (1.16%) की तुलना में काफी कम है। याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि आयातों की आवश्यकता अधिक मांग के मौसम के समय हुई थी और उस समय घरेलू उद्योग को क्षमता संबंधी अवरोध हुए थे। यह बताया गया है कि (क) याचिकाकर्ता के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है; (ख) आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा बनता है; और (ग) यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। अतः यह याचिका नियमों के अंतर्गत योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती है। इसके अलावा, भागीदार कंपनी पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

### ग.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

#### हांगकांग सरकार के अभ्यावेदन

13. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार (एच के एस ए आर जी) के ट्रेड एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा इस जांच शुरुआत के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए गए हैं :-

14. वर्तमान अभ्यावेदन के कार्य क्षेत्र में हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के विरुद्ध पाटनरोधी जांच के भारतीय प्राधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय प्राधिकारी को बाद में उपलब्ध होने वाली सूचना के आलोक में भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

15. हमें खेद है कि भारतीय प्राधिकारी ने जयश्री टेक्सटाइल द्वारा प्रस्तुत याचिका दस्तावेज के अगोपनीय अंश में प्रस्तुत किए गए अप्रमाणिक साक्ष्य और अवास्तविक तर्कों के आधार पर हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत की है।

16. एचकेएसएआरजी हांगकांग के विरुद्ध जयश्री टैक्सटाइल्स के आरोपों को पूर्णतः खारिज करती है। हमारा विचार यह है कि जयश्री टैक्सटाइल्स हांगकांग के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

17. हम यह मानते हैं कि भारतीय प्राधिकारी को जयश्री टैक्सटाइल्स की निराधार तर्कों के आधार पर हांगकांग के खिलाफ वर्तमान पाटनरोधी कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। हमारा यह विचार है कि हांगकांग के खिलाफ वर्तमान पाटनरोधी कार्रवाई शुरू करके भारतीय प्राधिकारी ने गैट 1994 ("डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI और खासकर उसके अनुच्छेद 5.3 के कार्यान्वयन संबंधी विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुसार कार्य नहीं किया है। हम डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के संगत प्रावधानों के अनुसार मामले की आगे पहल करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

18. हमारी मांग है कि भारतीय प्राधिकारी को हांगकांग के मूल के या वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी कार्रवाई तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए।

19. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3 के अंतर्गत भारतीय प्राधिकारी पर "इस बात की जांच करने के लिए कि क्या किसी जांच की शुरुआत को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और यथार्थता की जांच करने" का दायित्व है। जैसा कि हमने निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया है, हमने यह पाया है कि याचिका दस्तावेज में निहित सूचना वर्तमान पाटनरोधी कार्रवाई की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए अपर्याप्त है।

घ. अन्य मुद्दे :

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

क. अप्राधिकृत भागीदारी/अनुरोध और असमय अनुरोध

20. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान जांच में अनेक पक्षकार भा ले रहे हैं जो (क) उनके पक्ष में प्राधिकार के बिना और/या (ख) विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर उचित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत किए बिना (ग) जांच के विलंबित स्तर पर इस जांच में शामिल हो रहे हैं। हम एतद्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इसकी अनुमति नहीं दें।

ख. हांगकांग सरकार द्वारा किए गए अनुरोध

21. हांगकांग सरकार ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण में गलती की है। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि ऐसा तर्क देना किसी भी प्रतिवादी के लिए खुला है जो न तो निर्यातक हो और न ही विनिर्माता। इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। सामान्यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य को केवल निर्यातक अथवा वस्तुओं के निर्माता ही चुनौती दे सकते हैं। इसी बात को ए आई आई जी एम ए बनाम

निर्दिष्ट प्राधिकारी-2000 (119) ई एल टी 333 (टी) में न्यायाधिकरण द्वारा माना गया है। अतः हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे हांगकांग सरकार के इस तर्क को खारिज करें।

23. इसके अलावा, हलदर टोप्से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह माना गया है कि यदि प्रतिवादी प्राधिकारी के पास उपलब्ध किसी उचित तीसरे देश के आधार पर निर्यात कीमत बताता है तो उससे उनके उत्पाद का वास्तविक मूल्य सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा, गोपाल कृष्ण जी केतकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ एवं अन्य के मामले (1968 3 एससीआर 862) में न्यायालय ने यह भी माना है कि यद्यपि, सबूत का बोझ पक्षकार के ऊपर नहीं डाला जाता है, तथापि न्यायालय तब प्रतिकूल अनुमान लगा सकता है, यदि पक्षकार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास छुपाता है जो मामले में प्रस्तुत तथ्यों पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह उनके लिए एक ठोस प्रक्रिया नहीं है जो अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य को कतिपय कारणों से कोर्ट से छुपाकर रखना चाहते हैं। जिनसे विवादास्पद मुद्दों पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है और बल्कि सबूत के दायित्व के भावपूर्ण सिद्धांत पर भरोसा करते हैं।
24. यद्यपि उपर्युक्त निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के संदर्भ में था, तथापि यह यहां पर प्राधिकारी द्वारा की गई जांच पर भी समान रूप से लागू होता है, जिनका यह दायित्व है कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन करें और नियमावली के नियम 6(8) में बताई गई परिस्थितियों में प्रतिकूल अनुमान लगाने का उनके पास सांविधिक प्राधिकार भी है।

## घ.2 निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के एक आयातक को छोड़कर चीन और हांगकांग के किसकी भी उत्पादक/निर्यातक/उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।

## घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने इस संबंध में हांगकांग सरकार द्वारा दिए गए तर्कों और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की है। घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा :

27. प्राधिकारी ने हांगकांग (एचकेएसएआरजी) के ट्रेड डिपार्टमेंट द्वारा की गई समुक्तियों को नोट किया है। प्राधिकारी समुक्ति करते हैं कि इस विभाग को केवल दावा करने के बजाए उनके नियंत्रण के अधीन साक्ष्यों/तर्कों के साथ इन समुक्तियों की पुष्टि करनी चाहिए।

**ठ सामान्य मूल्य****ड1 बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी दावा, विश्लेषण और निष्कर्ष**

28. चीन के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है।

**ड2 चीन के लिए सामान्य मूल्य**

29. याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण इस वजह से कि संगत सूचना याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में मूल्य या परिकल्पित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता। भारत के लिए अन्य देशों की निर्यात कीमत को (क) ज्ञात आयातों की मात्रा काफी कम है (ख) अन्य देशों से आयात की कीमत संबद्ध देशों से आयातों के कारण प्रभावित हो सकती है, के कारण अन्य देशों से निर्यात की कीमत के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह नोट किया जाना चाहिए कि इस प्रकार का सामान्य मूल्य "ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में खपत के लिए निर्दिष्ट समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत" होना चाहिए। इस आधार पर सामान्य मूल्य निकालने के लिए प्राधिकारी के लिए ऐसे तीसरे देश में किसी सहयोगी उत्पादक द्वारा की गई समस्त घरेलू बिक्री से संबंधित पूर्ण एवं विस्तृत सत्यापन योग्य सूचना के साथ-साथ उत्पादन लागत अन्य सभी संबंधित सूचना तथा साक्ष्य (व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उपलब्ध समस्त सूचना सहित) की जरूरत होती है। याचिकाकर्ता का दावा है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के किसी उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

30. याचिकाकर्ता ने आगे यह दावा किया है कि एक प्रतिनिधि देश के रूप में भारत पर विचार किए जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक एवं पर्याप्त सूचना प्राप्त होगी। यह उल्लेख किया गया है कि अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा भी भारत को एक उचित प्रतिनिधि देश माना गया है। किसी भी हितबद्ध पार्टी ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। न ही किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में किसी अन्य देश का सुझाव दिया है।

30. याचिकाकर्ता द्वारा कई अन्य देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया जा रहा है। इनमें से काफी अधिक मात्रा में निर्यात मलेशिया को किए गए हैं। अतः इस बात पर विचार करते हुए कि जिस कीमत पर इस सामग्री की बिक्री निर्यात बाजार में खपत के लिए की जा रही है, मलेशिया में उसके फैब्रिक की पहुंच लागत के आधार पर सामान्य मूल्य 5.16 डॉलर/मीटर बनता है।

31. विकल्पतः चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमत और (ख) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विविधत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है। विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य 4.70 अम.डॉ./मीटर बनता है।

32. रिकार्ड में उपलब्ध समस्त सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने भारत को चीन के उत्पादकों के लिए एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। इस आधार पर सामान्य मूल्य 4.70 डॉलर प्रति मीटर बनता है।

### ड3 हांगकांग के मामले में सामान्य मूल्य

33. हांगकांग के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए जिस कीमत पर हांगकांग से वस्तु का आयात किया गया है, उस कीमत पर विचार करते हुए उसकी संबंधित प्रत्यक्ष लागत की भी वसूली नहीं हो सकी है। परिकल्पित सामान्य मूल्य के आधार पर हांगकांग में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था और इसीलिए उत्पादन लागत सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सर्वथा उचित पद्धति थी। चूंकि हांगकांग के किसी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए हांगकांग के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर किया गया है। इस आधार पर सामान्य मूल्य 4.70 अम.डॉ. प्रति मीटर बनता है।

### ड4 निर्यात कीमत:

34. आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त आयातों के मूल्य एवं मात्रा से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए भारत में भारित औसत आयात कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। चीन के किसी भी उत्पादक ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। एक आयातक मै. सेलीब्रिटी फैशन्स लि., चेन्नई को छोड़कर किसी भी आयातक/उपभोक्ता ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। मै. सेलीब्रिटी फैशन्स लि., चेन्नई द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राधिकारी ने सत्यापन किया था और यह पाया गया था कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान दोनों देशों से अज्ञात आयात की मात्रा 1,27,67,974 रही थी तथापि, इस प्रतिवादी आयातक द्वारा सूचित आयात केवल 3,23,660 मीटर के किए गए थे अर्थात् ये कुल ज्ञात आयातों के 2.53 % थे।

35. चूंकि सूचित किए गए आयातों की मात्रा काफी अधिक नहीं है और इसकी सूचना आईबीआईएस के आयात आंकड़ों में पहले ही दी जानी चाहिए थी, इसलिए निर्यात कीमत का निर्धारण आईबीआईएस द्वारा सूचित आयातों की भारित औसत आयात कीमत के आधार पर किया गया है। ये कीमतें सीआईएफ निर्यात कीमतें हैं। इन निर्यात कीमतों का सीआईएफ एवं कारखाना कीमत के बीच किए गए व्यय हेतु समायोजित किया गया है जिसका आधार याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे हैं। इन सीआईएफ निर्यात कीमतों में से निम्नलिखित व्यय घटाए गए हैं।

देश	डॉलर/मीटर
चीन	1.48
हांगकांग	2.14

### ड5 पाटन मार्जिन

36. कारखाना स्तर पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निवल निर्यात कीमत के आधार पर जांच अवधि के दौरान सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार है: -



## अम.डा.प्रात मोटर

	चीन	हांगकांग
सामान्य मूल्य	4.70	4.70
निर्यात कीमत	1.48	2.14
पाटन मार्जिन की राशि डॉ.	3.22	2.56
पाटन मार्जिन की राशि रूपए	132.59	105.09
पाटन मार्जिन %	219	120

37. प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए मुद्रा परिवर्तन दर अम.डॉ./रूपए= 40.75 ली है ।

#### ड 6 हांगकांग सरकार के अभ्यावेदन:

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआरजी) की सरकार के व्यापार और उद्योग विभाग द्वारा सामान्य मूल्य/निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए गए हैं ।

#### क. सामान्य मूल्य

39. याचिकाकर्ता ने न्यायसंगत कारण उपलब्ध कराए बिना परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । परिकलित सामान्य मूल्य की गणना की पद्धति भी नहीं बताई गई है ।

40. हम यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान हांगकांग से आयात की दर सबसे कम नहीं रही थी । हम यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा हांगकांग के लिए अनुमानित 191.66 भा.रू. या 4:7 अम.डॉ. प्रति मीटर का "परिकलित सामान्य मूल्य" फ्रांस (79.15 भा.रू.), यूनाइटेड किंगडम (129.75 भा.रू.) और आयरलैंड (142.86 भा.रू.) जैसे कुछ विकसित यूरोपीय देशों से उत्पादों की आयात कीमतों (आयात दरों) से काफी अधिक है । इन देशों की लागत (अनुमानतः आयात कीमत से कम) हांगकांग की कीमतों से सामान्यतः अधिक होनी चाहिए । इस " परिकलित सामान्य मूल्य" को हम अत्यधिक असामान्य और अनुचित मानते हैं । अतः अनुमान की सत्यता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ।

#### 6.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी ने हांगकांग के व्यापार विभाग (एचकेएसएआरजी) द्वारा व्यक्त अभिमतों का अध्ययन किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस विभाग को हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू कीमतों के साथ अपने अभिमतों की पुष्टि करनी चाहिए थी अथवा हांगकांग के कुछ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली के अनुसार सूचना प्रदान कर जांच में शामिल होना चाहिए था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हांगकांग के किसी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यापार विभाग ने भी हांगकांग में जांच अवधि के दौरान प्रचलित वैकल्पिक घरेलू कीमतें/निर्यात कीमतें भी प्रस्तुत नहीं की हैं ।

## च. क्षति निर्धारण और कारणात्मक संबंध की जांच

### च.1 घरेलू उद्योग के विचार

42. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :-

(क) भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बढ़ती रही थी। मांग में वृद्धि पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ा दी है तथापि, घरेलू उद्योग को अब काफी अप्रयुक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। इनमें देश में उत्पाद के भारतीय उत्पादन के संबंध में और भारत में इस उत्पाद की मांग/खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है।

(ग) पाटित आयातों के कारण काफी कीमत कटौती हुई है।

(घ) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग में पर्याप्त मात्रा में कम कीमत पर बिक्री हुई है।

(ङ) उस समय भी जबकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की इस उत्पाद की मांग और बिक्रियों, दोनों में वृद्धि हो रही थी, तब भी 2007-08 में बिक्रियों में वृद्धि मांग में हुई काफी वृद्धि की तुलना में मामूली थी।

(च) याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के उसके बाजार को कई खंडों में समूहबद्ध किया जा सकता है। ये हैं - खुदरा; थोक; आरएमजी (सिलेसिलाए वस्त्र), घरेलू; आरएमजी निर्यात; निर्यातक; एफआर/औद्योगिक एवं अन्य। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उपर्युक्त प्रत्येक बाजार खंड एक ऐसे बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी अपनी गतिशीलता होती है और उपर्युक्त समस्त बिक्री मात्रा से यद्यपि यह प्रतीत होगा कि इनमें क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हो रही थी, तथापि बिक्री मात्राएं घट रही थीं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि (क) खुदरा क्षेत्र की बिक्रियों में भारी वृद्धि हुई है (ख) थोक खंड में बिक्रियां 2005-06 और 2007-08 के बीच लगभग स्थिर रही हैं (ग) आरएमजी खंड में घरेलू बिक्रियां वस्तुतः घटी हैं। यह ऐसा खंड है जिसमें आयात सीधे घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा करते हैं (घ) प्रस्तावित जांच अवधि में सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात की बिक्रियों में भी गिरावट आई है। (ङ) घरेलू उद्योग के निर्यातों में घरेलू उद्योग के अथक प्रयासों के कारण वृद्धि हो रही है। (च) एफ आर ऐसा खंड है, जिसमें घरेलू उद्योग पाटन के कारण लगभग बर्बाद हो चुका है। (छ) औद्योगिक खंड भी पाटन के कारण प्रभावित हुआ है।

(छ) घरेलू उद्योग के औसत स्टॉक में वृद्धि हुई है।

(ज) घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग 2006-07 तक लाभ की स्थिति से वित्तीय घाटों की स्थिति में पहुंच गया है।

(झ) यद्यपि, बिक्रियों की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि बिक्री कीमत में 2005-06 तक वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई। परिणामस्वरूप 2005-06 में लाभों में वृद्धि हुई परंतु उसके बाद इनमें एक ऐसी स्थिति तक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को 2007-08 में वित्तीय घाटे झेलने पड़े।

(ञ) यद्यपि, आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है।

(ट) क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

(ठ) वर्ष 2005-06 में उत्पादकता में सुधार हुआ परंतु क्षमता में वृद्धि और पाटन के कारण उसका कम उपयोग हो पाने के चलते इसमें तत्परचात गिरावट आई।

(ड) घरेलू उद्योग की वृद्धि विशेष रूप से 2005-06 के बाद से अधिकांश मापदंडों की दृष्टि से ऋणात्मक रही है।

(ढ) संबंधित पाटित आयातों के दबाव के कारण घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति में विकृति आई है।

(ण) लाभ में सुधार के साथ वर्ष 2005-06 में निवेशों पर आय में वृद्धि हुई, परंतु बाजार में पाटित आयातों के परिणामस्वरूप उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आई।

## घ.2 हांगकांग का अभ्यावेदन

43. हांगकांग सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

(क) कुल मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में हांगकांग से हुए आयातों के हिस्से में कमी आई है।

(ख) हांगकांग से आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कमी आई है। अतः यह सिद्ध नहीं किया जा सकता या कम से कम यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हांगकांग से आयातों में सापेक्षिक दृष्टि से "भारी वृद्धि" हुई है।

(ग) हम यह नोट करते हैं कि यद्यपि, संयुक्त वस्तु की मांग में समूची अवधि के दौरान वृद्धि हुई (वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक 39% की वृद्धि), तथापि भारतीय घरेलू उद्योग की क्षमता में काफी अधिक दर से वृद्धि हुई (वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक 74% की वृद्धि)। इस बात को देखते हुए कि क्षमता में यह वृद्धि घरेलू उद्योग की क्षमता से दोगुनी थी, तथापि जब तक निर्यातों में वृद्धि द्वारा इस अंतर को पाटा नहीं जाता है, तब तक क्षमता उपयोग में गिरावट को महसूस करना अतर्कसंगत नहीं है। अधिक क्षमता विस्तार का तार्किक परिणाम निवेश पर आय में गिरावट, माल सूची में वृद्धि और इसके बाद बिक्री कीमत में कमी के रूप में होगा। क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप व्यय में अधिक ह्रास हुआ है जिसे अधिक विस्तार की स्थिति में लाभप्रदता के बारे में खराब प्रदर्शन माना जाएगा।

(घ) भारतीय बाजार में हांगकांग के हिस्से का प्रतिशत काफी कम बनता है, और ऐसे आयात केवल कीमत लेने वाले हो सकते हैं न कि कीमत निर्धारक ।

(ङ) इसके अलावा, हम यह नोट करते हैं कि याचिका दस्तावेज के अनुबंध 2.5 के रूप में संलग्न अन्य भारतीय उत्पादकों के किसी भी समर्थकारी पत्र में हांगकांग का उल्लेख नहीं किया गया है । वर्तमान अभ्यावेदनों में उल्लिखित कारणों के साथ-साथ हम यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है । हमारा भारतीय प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह हांगकांग के खिलाफ पाटनरोधी जांच को तुरंत समाप्त कर दें ।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

44. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हांगकांग के व्यापार विभाग (एचकेएसएआरजी) द्वारा व्यक्त अभिमतों का अध्ययन किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रवृत्ति संबंधी विश्लेषण की तुलना आधार वर्ष से किए जाने की जरूरत है । आधार वर्ष से हांगकांग से हुए आयातों की प्रवृत्ति में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है ।

### च.4 क्षति का संचयी निर्धारण

45. नियमावली के अनुबंध-II (III) के अनुसार जिन मामलों में एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है, उन मामलों में प्राधिकारी द्वारा उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन अपेक्षित होता है, जब वह यह निर्धारित करे कि:-

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन प्रत्येक देश से आयातों की निर्यात कीमत और उनकी मात्रा के 2% के रूप में व्यक्त समान उत्पादों के आयातों का 3% है और
- (ख) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात समान टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया हो ।
- (ग) प्राधिकारी ने यह पाया है कि आयातित संबद्ध वस्तु घरेलू रूप से उत्पादित फ्लैक्स फैब्रिक्स की वाणिज्यिक स्थानापन्न है ।

21. प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करना उचित है ।

46. आयातित वस्तु और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का आकलन करने के मद्देनजर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-

- (क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात समान टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया है;

(ख) प्राधिकारी ने पाया है कि आयातित संबद्ध वस्तु घरेलू रूप से उत्पादित फ्लेक्स फैब्रिक्स की वाणिज्यिक स्थानापन्न है ।

(ग) प्राधिकारी के पास प्रस्तुत सूचना इस बात का तर्कसंगत संकेत देती है कि संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि ये समान उत्पाद हैं ।

47. जैसा कि निम्नांकित तालिका में विस्तृत क्षति विश्लेषण से स्पष्ट है, संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है । संबद्ध आयातों में भारत में कुल आयातों, भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमत प्रभाव का संबंध है, आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही थी, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में लाभ के उचित स्तर की तुलना में वर्ष 2007-08 में उद्योग के लाभ में गिरावट आई और अंततः उसे वित्तीय घाटा हुआ । कीमत कटौती से कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण हुआ । वर्ष 2005-06 तक आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और उसके बाद उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में गिरावट आई । यदि बिक्रियों को खंडवार निर्दिष्ट किया जाए तो जहां घरेलू उद्योग की खुदरा बिक्रियों में वृद्धि हुई है, वहीं वर्ष 2005-06 के बाद सभी बिक्रियां स्थिर रही हैं और देश में उत्पाद की मांग में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद प्रस्तावित जांच अवधि में वास्तविक गिरावट आई है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन और हांगकांग से संवर्धित/सतत पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

48. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त है ।

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है (अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था) ।

50. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में निम्न दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी :-

(क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और

(ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव ।

51. पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों की कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती ।

52. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के संचयी प्रभाव और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, का मूल्यांकन किया जा सके।

53. चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए काफी अधिक पाटन मार्जिन निर्धारित किए गए हैं, इसलिए क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश से होने वाले सभी निर्यातों को पाटित आयात माना गया है।

#### च.5 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पादों का आयात या तो नगण्य रहा है या उसकी निर्यात कीमत अधिक रही है।

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की समग्र मांग में पर्याप्त सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत की पद्धति में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके।

#### क. मांग का आकलन

56. देश में उत्पाद की मांग या खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री एवं समस्त स्रोतों से आयातों की बिक्री की राशि के रूप में किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है।

आंकड़े लाख मीटर में

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
मांग/खपत	175.71	207.33	219.91	241.34
प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)	100	117	125	137
घरेलू उद्योग की क्षमता	38.16	44.64	49.68	66.24

भारत में संबद्ध उत्पाद में समूची क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हो रही थी। मांग में वृद्धि को देखते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। तथापि, घरेलू उद्योग अब पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता का सामना कर रहा है।

#### (ख) पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव : आयात की मात्रा एवं बाजार हिस्सा

57. इन वर्षों के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में आयात निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

आंकड़े लाख मीटर में

मांग	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घ.उ. की बिक्री	29.40	36.35	39.07	39.59
अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री	43.19	50.29	54.69	62.87
आयात-चीन/हांगकांग	76.63	92.40	107.22	125.3
आयात-अन्य देश	26.50	28.29	18.93	13.58
कुल मांग	175.72	207.33	219.91	241.34
सूचकांक	100	118	125	137
घ.उ. का उत्पादन	33.56	42.48	46.89	44.47
भारतीय उत्पादन	79.44	95.43	105.60	111.6
निम्नलिखित के संबंध में आयात का % हिस्सा				
कुल आयात	74.30	76.56	84.99	90.22
भारत में मांग	43.61	44.57	48.76	51.92
भारतीय उत्पादन	96.46	96.82	101.5	112.2

यह देखा जाता है कि :

- (क) आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है ;
- (ख) देश में उक्त उत्पाद के भारतीय उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है;
- (ग) आयातों में भारत में उत्पाद की मांग/खपत के संबंध में वृद्धि हुई है ।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटित आयातों से प्रतिकूल माक्रोअर्थिक प्रभाव प्रदर्शित होता है ।

### 4.8 आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

58. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में संवर्धनकारी प्रभाव कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

तुलना निम्नानुसार है:

	रु./मीटर	
	चीन	हांगकांग
निबल बिक्री प्रति	***	***
मध्य कीमत	74.69	105.25
कीमत कटौती	***	***
कीमत कटौती %	64.77	50.35

**(क) कीमत हास/न्यूनीकरण**

59. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में हास हो रहा है । चीन और हांगकांग से संबंध वस्तु की सीआईएफ आयात कीमत में क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में इतनी ही और आयातों की सीमा तक गिरावट आई है ।

**(ख) कम कीमत पर बिक्री**

60. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम है जिससे सकारात्मक रूप से अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हुई है ।

**(ग) घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड**

61. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि किसी क्षति जांच में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उत्पादन के कार्य निष्पादन की जांच करने से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । इसके अलावा, निम्नानुसार किए गए विस्तृत विचार-विमर्श के अनुसार वर्तमान स्थिति जारी रहने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है ।

**(क). उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग**

62. घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
क्षमता	***	***	***	***
क्षमता में वृद्धि		6.48	5.04	16.56
उत्पादन	33.56	42.48	46.89	44.47
उत्पादन में वृद्धि		8.91	4.41	(2.42)
क्षमता उपयोग	87.95	95.15	94.39	67.13
मांग	175.72	207.33	219.91	241.34
सूचकांक	100	118	125	137
मांग में वृद्धि		31.62	12.68	21.43

यह देखा जाता है कि:

(क) विचाराधीन उत्पाद की मांग में समूची क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है;



- (ख) मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं ;
- (ग) यद्यपि, घरेलू उद्योग वर्ष 2006-07 तक क्षमताओं में वृद्धि के अनुपात में अपना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम था, तथापि यह वर्ष 2007-08 के लिए सच नहीं निकला । वस्तुतः घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई जबकि क्षमता में वृद्धि हुई ।
- (घ) वर्ष 2007-08 में घरेलू उत्पाद के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई ।

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

लाख मीटर

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू बिक्री	29.40	36.35	39.07	39.59
बिक्री में वृद्धि		6.96	2.71	0.52
मांग में वृद्धि		31.62	12.58	21.43

63. यह देखा जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की मांग और बिक्री दोनों में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हो रही थी, तथापि वर्ष 2007-08 में बिक्री में यह वृद्धि मांग में बढ़ोत्तरी की तुलना में मामूली रही थी । इस प्रकार यद्यपि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की और उसके पास अप्रयुक्त क्षमता थी और बाजार में उत्पाद की मांग में वृद्धि हो रही थी तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में मामूली वृद्धि हो सकी ।

(ग) खंडवार विश्लेषण:

64. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के बाजार को कई खंडों में समूहबद्ध किया जा सकता है । ये हैं - खुदरा; थोक; आरएमजी(सिलेसिलाए वस्त्र), घरेलू; आरएमजी निर्यात; निर्यातक; एफआर/औद्योगिक एवं अन्य । याचिकाकर्ता का तर्क है कि उपर्युक्त प्रत्येक बाजार खंड एक ऐसे बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी अपनी गतिशीलता होती है और उपर्युक्त समस्त बिक्री मात्रा से यद्यपि यह प्रतीत होगा कि इनमें क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हो रही थी । तथापि, इनकी जांच खंडवार आधार पर नजदीकी से किए जाने की स्थिति में बिक्री मात्रा में गिरावट प्रतीत होती है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है ।

(लाख मीटर)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
खुदरा	4.29	6.24	6.85	8.28
थोक	5.74	9.44	9.88	9.38
आरएमजी घरेलू	10.16	12.39	11.58	11.76
आरएमजी निर्यात	7.35	6.80	10.62	9.06
एफआर	3.08	2.76	1.06	0.21
औद्योगिक	2.71	2.71	3.07	4.34

	33.34	40.34	43.06	43.04
	3.94	3.98	3.99	3.45
खुदरा खंड	28.40	36.35	39.07	39.59
	2.59	3.84	3.40	4.05
	35.98	44.18	46.45	47.70

65. निम्नलिखित तालिका में आयातकर्ता ने यह तर्क दिया है कि (क) खुदरा खंड में बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। (ख) खुदरा खंड में जिसमें कंपनी के अपने खुदरा आउटलेट हैं। (ख) वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक खुदरा खंड में बिक्री लगभग स्थिर रही है। यह ऐसा खंड है जिसमें आयात की मात्रा कम है। (ग) आरएमजी घरेलू में बिक्री में वस्तुतः गिरावट आई है। यह गिरावट घरेलू उद्योग से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। (घ) प्रस्तावित जांच अंतर्गत घरेलू उद्योगों में भी गिरावट आई है। आयात इस खंड में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। (च) घरेलू उद्योगों में घरेलू उद्योग के सतत प्रयास के कारण वृद्धि हुई है। (च) एफआर में घरेलू उद्योगों के कारण लगभग विलुप्त हो गया है। (छ) पाटन के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि हुई है।

66. निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग की बिक्री में उसकी अपनी खुदरा श्रृंखला के कारण वृद्धि हुई है। वस्तुतः यह घरेलू उद्योग की बिक्री को (क) खुदरा तथा (ख) अन्य में विभाजित किया गया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री बाजार में अत्यधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित स्थिर रहती रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देख जाएगा।

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	6.24	6.85	8.28	
खुदरा खंड	28.05	34.10	36.21	34.76
	33.34	40.34	43.06	43.04

तालिका-2

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
खुदरा खंड	100	145	160	193
अन्य खंड	100	117	125	120
कुल	100	121	129	130

(घ) निम्नलिखित तालिका

निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योगों के अनुसार रही हैं:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
औसत स्टॉक	6.57	8.50	11.85	14.48
सूचकांक	100	129	180	220
बिक्री दिवसों की संख्या के रूप में स्टॉक	75	77	102	121

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास औसत स्टॉक में वृद्धि हुई है ।

(ड) लाभ:

68. घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है । घरेलू उद्योग वर्ष 2006-07 तक लाभ की स्थिति से वित्तीय घाटे की स्थिति में आ गया है ।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बिक्री की लागत	रु./मीटर	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रु./मीटर	***	***	***	***
कर पूर्व लाभ	रु./मीटर	***	***	***	(***)
कर पूर्व लाभ	रु./लाख	***	***	***	(***)
पीबीआईटी	रु./लाख	***	***	***	***

सूचकांक

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
बिक्री की लागत	रु./मीटर	100	103	107	115
बिक्री कीमत	रु./मीटर	100	106	105	105
कर पूर्व लाभ	रु./मीटर	100	161	81	65

69. यद्यपि बिक्री लागत में हमेशा वृद्धि हुई, बिक्री कीमत में वर्ष 2005-06 तक वृद्धि हुई किंतु उसके बाद उसमें गिरावट आ गई । परिणामतः लागत में वर्ष 2005-06 तक वृद्धि हुई किंतु उसके बाद इसमें इतनी अधिक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2007-08 में वित्तीय घाटा उठाना पड़ा ।

70. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस आशा से अपनी क्षमता बढ़ाई थी कि वह देश में उत्पाद की सकारात्मक मांग में भागीदारी करेगा। तथापि, पाटित आयातों द्वारा उत्पन्न की गई अनुचित कीमत की स्थिति से कंपनी मांग में हुई वृद्धि से लाभ उठाने से वंचित हुई। यद्यपि घरेलू उद्योग ने इस आशा से निवेश किए थे कि वह अपनी लाभप्रदता में सुधार करेगी, तथापि देश में उत्पाद के अनुचित पाटन के कारण यह आशा विपरीत सिद्ध हुई।

(च) बाजार हिस्सा

71. भारत में मांग में घरेलू उद्योग और विभिन्न अन्य पार्टियों का हिस्सा निम्नानुसार रहा था:

आंकड़े % में

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू उद्योग	16.73	17.53	17.77	16.40
अन्य भारतीय उद्योग	24.58	24.26	24.87	26.05
कुल भारतीय उद्योग	41.31	41.79	42.64	42.45
संबद्ध देश	43.61	44.57	48.76	51.92
अन्य देश	15.08	13.64	8.61	5.63
कुल आयात	58.69	58.21	57.37	57.55
घरेलू उद्योग की कुल क्षमता/मांग	100	100	100	100

72. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2006-07 तक सुधार हुआ, परंतु जांच अवधि में गिरावट आई। बाजार हिस्से में यह गिरावट इस स्थिति में आई जहां (क) देश में मांग में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई; (ख) घरेलू उद्योग ने उच्चतर मांग की पूर्ति हेतु क्षमता में विस्तार किया। यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि चीन के आयातों द्वारा कीमत कटौती और उनका पाटन समूची क्षति अवधि में पाया गया है। क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा स्थिर रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग को क्षमताओं के विस्तार के कारण बाजार हिस्से में सुधार होने की आशा थी, तथापि इसने बाजार में पाटित आयातों के कारण बाजार हिस्से में स्थिरता/कमी की स्थिति का सामना किया।

(छ) रोजगार एवं मजदूरी

74. क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर रोजगार एवं मजदूरी में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	255	262	324	328
मजदूरी	रु./लाख	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी मजदूरी	रु.	***	***	***	***
सूचकांक		100	112	107	105

यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में प्रति कर्मचारी मजदूरी में वृद्धि हुई है ।

**(ज) उत्पादकता:**

75. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन जैसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है । उत्पादकता में वर्ष 2005-06 तक सुधार हुआ परंतु उसके बाद क्षमता वृद्धि एवं पाटित आयातों के कारण उसके कम उपयोग की वजह से लगातार गिरावट आई । याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वर्तमान स्थिति और घरेलू उद्योग के अद्यतन निष्पादन को देखते हुए घरेलू उद्योग उस स्थिति में अपनी उत्पादकता बनाए रखने में समर्थ नहीं होगा यदि पाटित आयात वर्तमान कीमतों पर जारी रहेंगे ।

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
उत्पादन	लाख मीटर	33.56	42.48	46.89	44.47
प्रति दिवस उत्पादकता	मीटर	9589	12136	13397	12705
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीटर	13161	16212	14473	13557
सूचकांक		100	112	110	103

**xiii) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

76. लागू सीमाशुल्क सहित संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत बिक्री प्राप्ति से बहुत कम है । पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है । परिणामतः यद्यपि उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि हुई है तथापि, वर्ष 2006-07 में बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम रही थी । इसके अलावा जहां उत्पादन लागत में वृद्धि हुई वहीं जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई, जिससे कीमत में ह्रास और उसमें न्यूनीकरण आया, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा ।

रु./मीटर

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
निवल बिक्री प्राप्ति	***	***	***	***
संबद्ध देशों के लिए पहुंच कीमत	58.68	69.91	81.13	77.59
उत्पादन लागत	***	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***	***
सूचकांक	100	101	92	94

**xiv) निवेश पर आय**

77. निवेश पर आय में वही प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है जैसी कि लाभ के संबंध में है। लाभ में वृद्धि के साथ वर्ष 2005-06 में निवेश पर आय में वृद्धि हुई परंतु तत्पश्चात बाजार में पाटित आयातों के कारण उसमें लगातार गिरावट आई।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
लाभ/हानि (पीबीआईटी)	रु./लाख	***	***	***	***
आरओसीई (जीएफए)	%	14.71	23.05	14.97	3.73
आरओसीई (एनएफए)	%	20.28	20.27	19.17	4.50
सूचकांक		100	149	95	0.22

**xv) नकद प्रवाह**

78. घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति में वही प्रवृत्ति दिखाई देती है जैसी कि लाभ के संबंध में। बढ्द पाटित आयातों के दबाव के कारण घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति खराब हुई। यह कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है। यद्यपि उद्योग नकद लाभ कमाने में सक्षम थे तथापि उसमें वर्ष 2005-06 तक सुधार हुआ और तत्पश्चात गिरावट आ गई।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
नकद प्रवाह	रु./लाख	उ.न.	***	***	(***)
नकद प्रवाह	प्रति/मीटर	उ.न.	***	***	(***)
नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	***
नकद लाभ	प्रति/मीटर	***	***	***	***
सूचकांक		100	150	102	0.22

**xvi) वृद्धि**

79. घरेलू उद्योग की वृद्धि खासकर वर्ष 2005-06 के बाद अधिकांश मापदंडों के संबंध में नकारात्मक रही है।

**च.7 हांगकांग के अभ्यावेदन :**

80. वग अनुबंध- 1.4 से यह नोट करते हैं कि हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक्स से संबंधित आयात एकड़े निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मीटर) (क)	मूल्य (भा.रु.) (रु)	दर (रु/क)	हिस्सा
2004-05	633,287	63,947,734	100.98	6.06
2005-06	986,220	89,214,724	90.46	7.80
2006-07	1,259,021	151,366,187	120.23	9.81
2007-08 (जांच अवधि)	1,521,020	123,413,060	93.42	9.15

81. डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 में भारतीय प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह "इस बात पर विचार करे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में आयातक सदस्य के उत्पादन या उसकी खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है।" इस संबंध में हांगकांग से आयातों के हिस्से में कुल मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है (याचिका दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतरण का पृष्ठ-16)

82. याचिका दस्तावेज में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार हमने भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में हांगकांग से आयातों की गणना निम्नानुसार की है :

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
आयात मात्रा (लाख मीटर)	6.33	9.86	12.69	13.21
निम्नलिखित के संबंध में आयातों का हिस्सा				
भारत में कुल आयात %	6.06	7.80	9.81	9.15
भारत में मांग %	3.57	4.63	5.67	5.35
भारतीय उत्पादन %	7.97	10.33	11.92	11.83

83. उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि हांगकांग से हुए आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादन या खपत के अनुपात में गिरावट आई है। अतः इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती या यह कम से कम अनिर्णायक है कि तुलनात्मक दृष्टि से हांगकांग से आयातों में "पर्याप्त वृद्धि" हुई है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

क्षति संबंधी जांच आधार वर्ष से की गई है। आधार वर्ष से हांगकांग से हुए आयातों में लगभग 3% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

### छ. कारणात्मक संबंध

84. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुबंध-II के पैरा (V) के अनुसार प्राधिकारी ने सूचीबद्ध ज्ञात कारकों और घरेलू उद्योग की स्थिति पर उनके परिणामों की जांच की है। पाटित आयातों से भिन्न ज्ञात कारकों, जिनसे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, की जांच भी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन अन्य कारकों से हुई संभावित क्षति पाटित आयातों की वजह से नहीं हुई है।

### छ.1 अन्य ज्ञात कारकों की जांच

#### क. अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पादों का आयात या तो नगण्य रहा है या उसकी निर्यात कीमत अधिक रही है।

## ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं हुई है । इसके विपरीत क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की समग्र मांग में पर्याप्त सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत की पद्धति में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके ।

## ग. विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और प्रतिस्पर्धा

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का एकमात्र ऐसा बाजार है जहां संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं । विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों के आयातों की बिक्री घरेलू उत्पादकों द्वारा बेची गई वस्तु के रूप में उसी बाजार में की जा रही है । प्राधिकारी की जानकारी में विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों और उनके बीच प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य नहीं आया है ।

## घ. प्रौद्योगिकी में विकास

88. रिकॉर्ड की जांच के आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संगत कारक नहीं रहा है ।

## ङ. निर्यात निष्पादन

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है । निर्यात मात्रा में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण प्रतीत नहीं होता है ।

## च. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

90. जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है ।

## छ. कारणात्मकता के बारे में निष्कर्ष

91. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटित आयातों द्वारा हुई क्षति की तुलना में घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से क्षति नहीं हुई है और यदि हुई है तो वह नगण्य है (उपर्युक्त पैरा 47)। घरेलू उद्योग की स्थिति से क्षति अवधि के दौरान वास्तविक गिरावट का पता चलता है जो मुख्यतः पाटित आयातों के कारण आई है । बिक्री मात्रा में इष्टतम वृद्धि के कारण पाटित आयातों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग अपने उत्पादन तथा क्षमता उपयोग, पाटित आयातों द्वारा कीमत कटौती में सुधार करने से वंचित हुआ है जिसकी वजह से लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट आई है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है । प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।



**ज. क्षति मार्जिन की मात्रा**

92. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देश से निर्यातों की भारत औसत पहुंच कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :-

**क्षति मार्जिन संबंधी गणनाएं**

	रु./मीटर	
	चीन	हांगकांग
पहुंच मूल्य	74.69	105.25
क्षति रहित कीमत	***	***
क्षति मार्जिन	162.59	132.03

**झ. प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियां****घरेलू उद्योग के अनुरोध**

93. (i) यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग फ्लैक्स की 50% से कम मात्रा वाली फैब्रिक्स का उत्पादन और बिक्री करता रहा है। जांच की प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता ने किस्मवार फैब्रिक उत्पादन को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया है। यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता ने 30% से कम फ्लैक्स मात्रा वाली फ्लैक्स फैब्रिक का उत्पादन किया है। अतः प्रकटन विवरण की समीक्षा करने और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के भीतर 30% से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाली फ्लैक्स फैब्रिक को शामिल करने का अनुरोध किया जाता है।

- (ii) हांगकांग द्वारा किए गए अनुरोध विभिन्न कारणों की दृष्टि से अव्यवहार्य हैं।
- (iii) याचिकाकर्ता यार्न का विनिर्माण करता है और इनकी खपत फैब्रिक बनाने में स्वयं ही करता है। यह अनुरोध किया जाता है कि केवल कैप्टिव अंतरण दर पर विचार किए जाने की जरूरत है।
- (iv) जब जांच अवधि के औसत से विनिमय दर अधिक हो, तो शुल्क को अमरीकी डॉलर के रूप में होना चाहिए। यह शुल्क भारतीय रूपए में तब होना चाहिए जब विनिमय दर जांच अवधि के औसत से कम हो जाती है।

**94. प्राधिकारी द्वारा जांच**

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेड वार उत्पादन विवरण के अनुसार घरेलू उद्योग ने 30-50% की फ्लैक्स मात्रा वाली फैब्रिक का उत्पादन किया है। यह कुल उत्पादन का 0.62% है। चूंकि घरेलू उद्योग 50% तक की फ्लैक्स मात्रा वाली फैब्रिक का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 50% से अधिक फ्लैक्स मात्रा का उत्पाद विचाराधीन उत्पाद है। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अन्य तर्कों पर इन जांच परिणामों में विधिवत ढंग से विचार किया गया है।

## छ.2 भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

95. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों द्वारा कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है और भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ज. निष्कर्ष :

97. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्रकटन विवरण या अन्यथा के संबंध में की गई टिप्पणियों समेत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में रिकॉर्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान पाटन और क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

- i. संबद्ध देशों के मूल से पाटित कीमतों पर आयात हुए हैं और इनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ii. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं उनके सामान्य मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और आवेदकों की संबद्ध वस्तु की निवल बिक्री प्राप्ति से कम कीमतों पर लाई गई हैं और इनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- iii. संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट ने घरेलू उद्योग को मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी विक्रियों में वृद्धि करने से रोका है।
- iv. भारी कीमत कटौती और पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि से लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय की दृष्टि से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- v. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि (समग्र रूप से तथा मांग में हिस्से की दृष्टि से) के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है।

98. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार प्राधिकारी चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के/अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। पाटनरोधी शुल्क निम्नांकित तालिका के कालम-8 में दर्शायी गई राशि और आयातों/किग्रा. की पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नांकित देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के सीमाशुल्क उप शीर्ष 53.09, अध्याय 53 के अंतर्गत आने वाले फ्लैक्स फैब्रिक्स के सभी आयातों पर लागू होगा।

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	53.09	फ्लैक्स फैब्रिक	चीन	चीन	कोई	कोई	206.24	मीटर	रुपए
3	53.09	-वही-	चीन	कोई	कोई	कोई	206.24	मीटर	रुपए
4	53.09	-वही-	कोई	चीन	कोई	कोई	206.24	मीटर	रुपए
5	53.09	-वही-	हांगकांग	हांगकांग	कोई	कोई	209.72	मीटर	रुपए
6	53.09	-वही-	हांगकांग	कोई	कोई	कोई	209.72	मीटर	रुपए
7	53.09	-वही-	कोई	हांगकांग	कोई	कोई	209.72	मीटर	रुपए

99. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलनीय मूल्य अभिप्रेत है और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3, 8 ख, 9 तथा 9 के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल हैं।

100. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी 17 फरवरी, 2009 के अनंतिम जांच परिणामों तथा 27 फरवरी, 2009 की शुद्धि पत्र अधिसूचना की पुष्टि करते हैं और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख से उपर्युक्त पैरा और उपर्युक्त शुल्क तालिका के में उल्लिखित पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं।

101. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2009

**Final Findings**

**Subject: Anti Dumping Duty Investigations concerning imports of Flax Fabrics originating in or exported from China PR & Hong Kong.**

**F No. 14/08/2008-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

**A. PROCEDURE**

A. 1 The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:

- a. On 3<sup>rd</sup> October, 2008, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) issued an initiation Notification, duly notifying the same in the Gazette of India, thereby initiating an Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as subject country).
- b. The Designated Authority notified Preliminary Findings vide notification dated 17/02/2009 with regard to anti-dumping investigations concerning imports of Flax Fabrics originating or exported from China PR & Hong Kong and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- c. The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the said findings within forty days from the date of the letter;
- d. The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 18<sup>th</sup> May 2009. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rejoinders, if any.
- e. The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties:

- t. The arguments raised by the petitioners and other interested parties have been appropriately dealt with in these findings;
- g. In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 16<sup>th</sup> September 2009 and comments received on the same, have been duly considered in these findings;
- h. \*\*\* in this notification represents information furnished by an interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- i. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April, 2007 to 31st March, 2008 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from April 2004-March 2005, April 2005-March 2006, April 2006-March 2007 and the POI.
- j. The Authority provided opportunity to the importers/ industrial users of the product under consideration to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.
- k. The Authority satisfied itself with regard to accuracy of the information provided by the interested parties to the extent considered necessary.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **B.1. Views of the Domestic industry**

2. The Product under Consideration is woven fabric having more than 30% flax content. Flax and linen are synonyms and the word "flax" is also known as "Linen" and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is also often used as in generic term to describe a class of woven bed, bath, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets, etc. In the past, the word also referred to light weight undergarments such as shirts, chemises, waist shirts, lingerie and detachable shirt collars and cuffs.

6. The product under consideration is classified under Customs Tariff Chapter 53 at sub-heading 53.09. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

7. The applicants have claimed that goods produced by them are like article to the goods originating in or exported from China and Hong Kong. The imported product is also used by same category of consumers. The product contains the same basic technical properties and has the same functions & uses. There is no known difference in Flax Fabric produced by the Indian industry and subject Flax Fabric imported in India. Flax Fabric produced by the Indian industry and imported in India are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the domestic industry are being considered as like article to the goods imported from the subject countries.

## **B.2. Views of the Importers, Consumers, exporters and Other Interested Parties**

8. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties have filed any comment or submissions with regard to the product under consideration, and the like articles.

## **B.3. Examination by the Authority**

9. The product under consideration is flax fabric originating in or exported from china PR and Hong Kong is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is often used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at sub-heading 53.09. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

10. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that like article means an article, which is identical and alike in all respects to the product under consideration or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

11. The petitioner claimed that the goods produced by them are like article to the goods originating in or exported from the subject countries. The Authority notes that the Domestic Industry has not been producing substantially woven fabric having more than 30% flax content. During the POI, the production of woven fabric having more than 30% flax content was merely 0.62% of the total production, hence not substantial. However, the Domestic Industry has been majorly producing woven fabric having more than 50% flax content. The woven fabric (having more than 50% flax contents) produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those imported flax fabric from subject countries. In view of the above the authority hold that woven fabric (having more than 50% flax contents) produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the Product under Consideration within the meaning of the rules for the purposes of this finding.

## **C. DOMESTIC INDUSTRY**

### **C.1. Views of the Domestic Industry**

12. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the standing of the Domestic Industry.

i. The application has been filed by M/s Jaya Shree Textiles (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.) India and is supported by seven other manufacturers namely. a) Govardhan overseas

Pvt. Ltd., b) VSM Weaves India Ltd. c) V.S. Palaniswamy Company, d) Vasanthi Fabrics e) Mahendra Textiles f) Mars Export, Karur g) Ram Textiles, Karur. The petitioner has imported Flax fabric from China during the POI and the injury period. However, the import is insignificant as compared to production by the company (6.27%) and consumption (1.16%) in India. It has been stated by the petitioner that the imports were necessitated at the time of peak season and capacity constraints with the domestic industry at that stage. It has been seen that (a) production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production; (b) domestic producers expressly supporting the application account for significantly more than 50 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry; and (c) the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The petition therefore, satisfies the requirement of standing under the Rules. Further, the participating company constitutes domestic industry within the meaning of the Anti Dumping Rules.

## **C.2. Views of the Exporter, Importer, consumer and Other Interested Parties**

### **Representations by Hong Kong Government:**

13. The following representations are made by The Trade and Industry Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) with respect to this initiation.

14. The scope of the present representations covers the Indian Authority's AD proceedings against flax fabrics originating in or exported from Hong Kong. Further, representations may be submitted to the Indian Authority in the light of information, which may become available at a later date.

15. We regret that the Indian Authority has initiated the AD investigation against imports of flax fabrics originating in or exported from Hong Kong based on unsubstantiated evidence and flimsy arguments as presented in the non-confidential version of the petition document filed by Jaya Shree Textiles.

16. HKSARG wholly rejects Jaya Shree Textiles' allegations against Hong Kong. We are of the view that Jaya Shree Textiles failed to provide sufficient evidence to justify the initiation of the AD investigation against Hong Kong.

17. We consider that the Indian Authority should not have initiated the current AD proceedings against Hong Kong based on Jaya Shree Textiles' flimsy arguments. We are of the view that by initiating the current AD proceedings against Hong Kong, the Indian Authority has not acted in accordance with the World Trade Organisation Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 ("the WTO AD Agreement"), particularly its Article 5.3. We reserve our right to pursue the case further in accordance with the relevant provisions of the WTO AD Agreement.

18. We demand that the Indian Authority should terminate the AD proceedings against the imports of flax fabrics originating in or exported from Hong Kong immediately.

19. The Indian Authority is obliged under Article 5.3 of the WTO AD Agreement to “*examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation*”. As we elaborate in the following paragraphs, we have found that the information contained in the petition document is inadequate to justify initiation of the current AD proceedings.

#### **D. OTHER ISSUES**

##### **D.1. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

###### **a. Unauthorized participation/submission and untimely submissions**

20. Petitioner submits that a number of parties seem to be participating in the present investigations without providing (a) authorization in their favour; and/or (b) relevant information in the form and manner prescribed within specified time limits, (c) entering into investigations at such a belated stage of the proceedings. We hereby request the Designated Authority not to permit these.

###### **b. Submissions made by Hong Kong Government**

21. The government of Hong Kong contends that the Authority has erred in fixing the normal value. It is to be noted in this regard that such a contention is not open to the contender who is neither an exporter nor a manufacturer. In this case, Designated Authority has followed the procedure prescribed under Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules; 1995. Normally, only the exporter or the manufacturer of the articles can challenge the value fixed by the Designated Authority. The same has been held by the Tribunal in *AIIGMA v. Designated Authority-2000* (119) E.L.T. 333 (T). We, therefore request the Authority to reject this contention of the Hong Kong Government.

23. Further, it has been held in *Halder Topse* Supreme Court Judgement that if the respondent makes the export price based on an appropriate third country available to the Authority then it could have established the actual normal value of their product. Further, in *Gopal Krishnaji Ketkar v. Mahomed Haji Latiff & Others* (1968 3 SCR 862) court has further held that even if the burden of proof does not lie on a party the court may draw an adverse inference if he withholds important documents in his possession which can throw light on the present facts in issue. It is not a sound practice for those desiring to rely upon a certain state of affairs to withhold from the court the best evidence that is in their possession, which could throw light upon the issues in controversy than to rely upon the abstract doctrine of onus of proof.

24. Though the above decision was with reference to a proceeding in court of law, the same is equally applicable to the investigation conducted by the authority herein which has the duty of appreciating the evidence placed before it and also has the statutory authority of drawing adverse inference in the circumstances enumerated in Rule 6 (8) of the Rules.



## **D.2. VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

25. The Authority notes that none of the producers/ Exporters/Consumers and other interested parties except one importer of the subject goods in China and Hong Kong has responded to the Designated Authority.

## **D.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

26. The Authority has examined the contentions made by Government of Hong Kong in this regard as well as the evidence available on record. With regard to standing of the domestic industry, Rule 2(b) states as under:

*“Domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry.*

27. The Authority notes the observations made by the Trade Department of Hong Kong (HKSARG). The Authority observes that the Department should have substantiated the observations with evidence/ facts under their control instead of mere assertions.

## **E. NORMAL VALUE**

### **E.1 MARKET ECONOMY TREATMENT CLAIM, ANALYSIS AND FINDINGS**

28. None of the Chinese exporters has responded to the initiation notification.

### **E.2. NORMAL VALUE FOR CHINA**

29. The Petitioner submits that normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available to the Petitioner. Export price from other countries to India cannot be adopted for the reasons that, (a) volume of known imports are quite low (b) import price from other countries could be affected due to imports from subject countries. It should be noted that such normal value must be ‘comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in such market economy third country’. In order to arrive at normal value on this basis, the Authority shall require complete & exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidences (including all information in the ordinary course of trade). Petitioner has claimed that it has not been able to procure such information from a producer in market economy third country.

30. Petitioner has further claimed that consideration of India as a surrogate country would result in access to accurate and adequate information. It has been pointed out that India has been considered as an appropriate surrogate country by other Investigating Authorities also. None of the interested parties have made any submissions in this regard. Nor any other interested party has suggested any other country as an appropriate market economy third country.

30. Petitioner has been exporting the product under consideration to a number of countries. Amongst these, significant exports are being made to Malaysia. Therefore, considering that the price at which the material is being sold for consumption in the export market, the normal value on the basis of landed cost of its fabric in Malaysia comes to \$5.16/ mtr.

31. Alternatively, normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. Normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted comes to US\$ 4.70 per meter.

32. Considering all the information on record, the Authority has adopted India as an appropriate market economy country for Chinese Producers. Normal value on this basis comes to 4.70\$ per meter.

### **E.3. NORMAL VALUE IN CASE OF HONG KONG**

33. None of the producers/exporters in Hong Kong has responded to the Authority. Petitioner would like to determine normal value in case of Hong Kong on the basis of constructed normal value, claiming that considering the price at which goods have been imported from Hong Kong, the same would not have permitted recovery of even associated direct costs and therefore cost of production was the most appropriate methodology for determination of normal value. Since none of the exporters from Hong Kong has responded to the Authority and further since there is no other information available to the Designated Authority, normal value in case of Hong Kong has been determined on the basis of estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative expenses and profits. The normal value on this basis comes to US\$ 4.70 per meter.

### **E.4. EXPORT PRICE:**

34. Export price has been determined on the basis of weighted average import price into India, considering the information on volume and value of imports provided by IBIS. None of the Chinese producers have responded to the Designated Authority with verifiable information. Barring an importer M/s Celebrity Fashions Ltd. Chennai, none of the importers/consumers responded to the Authority with verifiable information. The information provided by M/s Celebrity Fashions Ltd. Chennai was examined by the Authority and it was found that whereas the known volume of imports during the investigation period was 1,27,67,974 meters from both the countries, imports reported by this responding importer accounts for 3,23,660 meters only, i.e., 2.53 % of total known imports.

35. As the quantity of imports reported is not very substantial and it might have already been reported under the IBIS import data, the export price has been determined on the basis of weighted average import price of the imports reported by the IBIS. These prices are CIF export prices. These export prices have been adjusted for expenses incurred between CIF and ex-factory, based on the claims made by the petitioner. The expenses on account of Ocean freight, Marine Insurance and others have been reduced from these CIF export prices. The net ex-factory export price, after adjustment of the above expenses is as follows:

Country	\$/Mtr
China	1.48
Hong Kong	2.14

### **E.5. DUMPING MARGIN**

36. On the basis of normal values and net export prices determined as explained above at ex-factory level, the dumping margin during POI for all exporters are as per table below: -

US \$ Per Mtr		
Particulars	China	Hong Kong
Normal Value	4.70	4.70
Export price	1.48	2.14
Dumping margin amount \$	3.22	2.56
Dumping margin amount Rs.	132.59	105.09
Dumping margin %	219	120

37. The authority has adopted currency conversion rate for the POI as US \$/ RS= 40.75.

### **E.6. Representations by Hong Kong Government:**

38. The following representations are made by The Trade and Industry Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) with respect to Normal value/export price and dumping margin.

#### **(A) Normal Value**

39. The petitioner has determined the normal value on the basis of constructed value without providing justifiable reasons. The methodology to calculate the constructed normal value is also not disclosed.

40. We note that during the Period of Investigation, the rate of imports from Hong Kong was not amongst the lowest ones. We also note that the "constructed normal value" per Mtr for Hong Kong is INR 191.66 or US\$ 4.7 per mtr. For Hong Kong estimated by the petitioner is much higher than the import prices (rates of imports) of the products from certain countries, such as France (INR 79.15), United Kingdom (INR 129.75) and Ireland (INR 142.86), whose

costs (presumably lower than the import prices) should generally be higher than those in Hong Kong. This "constructed normal value" we considered highly unusual and not reasonable. The accuracy and reliability of the estimation are, therefore, questionable.

### **6.1 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

41. The Authority has gone through the observations made by the trade department of Hong Kong (HKSARG). The Authority notes that the department should have substantiated their observations with the domestic prices of the PUC in Hong Kong or certain exporters from Hong Kong should have participated by providing information as per the exporter's questionnaire. The authority notes that no exporter has responded from Hong Kong or the Trade department has also not furnished alternative domestic prices/ export prices prevalent during the POI in Hong Kong.

## **F. INJURY DETERMINATIONS AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**

### **F.1. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

42. The following are the views of domestic industry:-

- a) Demand of the subject product in India was increasing throughout the injury period. Considering the increase in demand, the domestic industry has enhanced its capacity. However, the domestic industry is now faced with significant unutilized capacities.
- b) Imports have increased in absolute terms. They have increased in relation to Indian production of the product in the Country and also in relation to demand/consumption of the product in India.
- c) There is no significant price undercutting due to dumped imports.
- d) There is no significant price underselling in the domestic industry due to dumped imports.
- e) Even when both demand and sales of the domestic industry for the product were increasing over the injury period, the increase in sales in 2007-08 was marginal as compared to significant increase in demand.
- f) Petitioner argued that its market for the product under consideration could be grouped into a number of segments. These are Retail; Whole Sale; RMG (Ready made Garment), Domestic RMG Export; Export; FR/Industrial and Others. Petitioner argued that each of the above market segment represents a market with its own dynamics and while it would appear from the above overall sales volumes that the same were increasing over the injury period, sales volumes declined. Further, petitioner argued that (a) sales in the retail segment have increased significantly. (b) Sales in the wholesale segment have almost stagnated between 2005-06 and 2007-08. (c) Sales in RMG domestic have in fact declined. This is the segment where the imports are directly competing with the domestic industry. (d) Sales in RMG exports have also declined in proposed POI. (e) Exports of the domestic industry have been growing due to persistent efforts of the domestic

industry. (f) FR is a segment where the domestic industry has almost got vanished due to dumping. (g) Industrial segment is also affected due to dumping.

g) Average stocks with the domestic industry have gone up.

h) Profits of the domestic industry declined. The domestic industry has gone into a situation of financial losses from a situation of profits upto 2006-07.

i) Whereas the cost of sales increased throughout, selling price increased upto 2005-06, but declined thereafter. Consequently, profits increased in 2005-06, but declined thereafter significantly to such a situation that the domestic industry suffered financial losses in 2007-08.

j) Whereas the market shares of the imports have increased, that of the domestic industry has declined.

k) Employment and wages have increased in view of additions to the capacity.

l) Productivity improved in 2005-06, but declined consistently thereafter with the addition of capacities and lower utilization thereof due to dumped imports.

m) The growth of the domestic industry is negative in terms of most of the parameters, more particularly after 2005-06.

n) Due to pressure from subject-dumped imports, cash flow situation of the domestic industry has deteriorated.

o) Return on investment increased in 2005-06 with the improvement in profits, but consistently declined thereafter as a result of dumped imports in the market.

## **F.2. REPRESENTATION FROM HONG KONG:**

43. Following are the submissions made by the Government of Hong Kong:

a) The share of imports from Hong Kong has decreased as compared with the same period last year despite of the increase in total demand.

b) The imports from Hong Kong have decreased in relation to the production or consumption in India during the POI as compared with the previous year. Therefore, it cannot be established, or at least is inconclusive, that there has been a 'significant increase' in imports from Hong Kong in relative terms.

c) We note that while the demand of the subject product increased throughout the period (increased by 39% from 2004-05 to 2007-08), the capacity of the Indian domestic industry grew at a much higher rate (increased by 74% from 2004-05 to 2007-08). Given

that the growth in capacity was almost double of that of the domestic demand, it is not unreasonable to experience decrease in capacity utilization unless the growth in exports could make up the difference. The logical consequence of over expansion would be declining return on investment, increasing in inventories, and in turn, suppression of selling price. Expansion of capacity also resulted in greater depreciation expenses, which would translate into poor performance on profitability in the event of over expansion.

d) Hong Kong only accounted for a small percentage of the Indian market, and such imports can only be a price taker instead of a price setter.

e) Furthermore, we notice that Hong Kong has not been mentioned in any of the supporting letters from other Indian producers enclosed as Annexure – 2.5 of the petition document. The petitioner has failed to provide sufficient and reliable evidence to justify the initiation of the AD Investigation. We urge the Indian Authority to terminate the AD Investigation against Hong Kong immediately.

### **F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

44. The authority has gone through the observations made by the Trade Department of Hong Kong (HKSARG) in respect of Injury. The Authority notes that the trend analysis needs to be compared from the base year. The trend of imports from Hong Kong shows an upward trend from the base year.

### **F.4. CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY**

45. As per annexure-II (iii) of the Rules, in case, imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that-

a) The margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article, and,

b) The subject goods have been imported from the subject countries under the same tariff classification;

c) The Authority has found that the imported subject goods are commercial substitutes of the domestically produced Flax Fabrics.

21. The Authority holds that it is appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

46. With a view to assess the conditions of competition between imported products and the like domestic product, the Authority notes that -

- a) The subject goods have been imported from the subject countries under the same tariff classification;
- b) The Authority has found that the imported subject goods are commercial substitutes of the domestically produced Flax fabric.

c) The information furnished to the Authority gives a reasonable indication that the exports made from the subject countries compete in the same market, as these are like products.

47. As is evident from the detailed injury analysis in tables below, imports of subject goods increased significantly in absolute terms. Subject imports increased significantly in relation to total imports into India, production and consumption in India. With regard to price effect, imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market, increase in selling price of the domestic industry were far below than the increase in cost of production resulting in decline in profits and eventually financial losses in 2007-08 from a situation of a reasonable level of profit in the year 2005-06. Price undercutting resulted in price suppression as well as price depression. Performance of the domestic industry in terms of economic parameters improved till 2005-06 and thereafter deteriorated in terms of production, capacity utilization, selling price, profits, cash profit and return on investments. Market share declined and inventories increased throughout the injury period. If sales are segmented, while retail sales of the domestic industry increased, rest of all sales stagnated after 2005-06 and in fact declined in the proposed POI in spite of significant increase in demand of the product in the Country. It is thus evident that the domestic industry has suffered material injury as a result of increased/continued-dumped imports from China PR and Hong Kong.

48. Therefore, the Authority notes that it is appropriate to, cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article, in the light of conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

49. The Authority has taken note of various arguments put forth by the Domestic Industry (There was no response from other interested parties).

50. Annexure II of the AD Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of both:

a) The volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and

b) Consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

51. The Authority while examining the volume of dumped imports is required to examine whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

52. For the purpose of injury analysis the Authority has examined cumulative effect of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on all

relevant Economic factors and indices having a bearing on the state of industry to evaluate the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

53. Since significant dumping margins have been established for the exports from the subject countries, entire exports from the subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

#### **F.5. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS AND IMPACT ON DOMESTIC INDUSTRY**

54. The Authority notes that the imports of product under consideration from other countries are either negligible or the export price is higher.

55. The Authority notes that there is no contraction in the demand during POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown significant positive growth during the injury period. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which could be attributed to the injury to the domestic industry.

#### **A) ASSESSMENT OF DEMAND**

56. The demand or consumption of the product in the Country has been determined as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below:

	Figures in Lac Mtr			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Demand/ Consumption	175.71	207.33	219.91	241.34
Trend (indexed)	100	117	125	137
Capacity of the Domestic Industry	38.16	44.64	49.68	66.24

Demand of the subject product in India was increasing throughout the injury period. Considering the increase in demand, the domestic industry has enhanced its capacity. However, the domestic industry is now faced with significant unutilized capacities.

#### **B) VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS: IMPORT VOLUMES AND MARKET SHARES**

57. Volume of dumped imports has increased over the years. The imports in relation to production and consumption in India are given in the table below:

	Figures in Lac Mtr			
Demand	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Sales of DI	29.40	36.35	39.07	39.59
Sales of other Indian products	43.19	50.29	54.69	62.87
Import-China/Hong Kong	76.63	92.40	107.22	125.3
Import-other countries	26.50	28.29	18.93	13.58
TOTAL DEMAND	175.72	207.33	219.91	241.34



INDEX	100	118	125	137
Production of DI	33.56	42.48	46.89	44.47
Indian production	79.44	95.43	105.60	111.6
%Share of import in relation to				
Total imports	74.30	76.56	84.99	90.22
Demand in India	43.61	44.57	48.76	51.92
Indian production	96.46	96.82	101.5	112.2

It is seen that:

- Imports have increased in absolute terms;
- Imports have increased in relation to Indian production of the product in the Country;
- Imports have increased in relation to demand/consumption of the product in India.

In view of the above, it is concluded that dumped imports show adverse volume effect.

#### **F.6. PRICE EFFECT OF IMPORTS**

58. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

The comparison is as follows:

	Rs/Mtr	
	China	Hong Kong
Net sales realization	***	***
Landed Price	74.69	105.25
Price Undercutting	***	***
% Price undercutting	64.77	50.35

#### **A) PRICE SUPPRESSION/DEPRESSION**

59. Dumped imports are depressing the prices of the domestic industry. CIF import price of the subject goods from China and Hong Kong have declined continuously over the injury period. The selling prices of the domestic industry have declined in the same direction and to the same extent as that of imports.

#### **B) Price underselling**

60. Landed price of imports is significantly below the non-injurious price of the domestic industry resulting in significantly positive underselling.

#### **C) Economic Parameters of The Domestic Industry**

61. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers

of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Petitioner has submitted that examination of performance of the domestic industry would reveal that the domestic industry has suffered material injury. Further, the domestic industry is threatened with material injury, should the present condition continue, as discussed in detail herein under.

**a) Production, capacity and capacity utilization**

62. Actual production, capacity and capacity utilization of the domestic industry have been provided in the following table.

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Capacity	***	***	***	***
Increase in capacity		6.48	5.04	16.56
Production	33.56	42.48	46.89	44.47
Increase in production		8.91	4.41	(2.42)
Capacity utilization	87.95	95.15	94.39	67.13
Demand	175.72	207.33	219.91	241.34
Index	100	118	125	137
Increase in demand		31.62	12.58	21.43

It is observed that:

- (a) demand for the product under consideration increased throughout the injury period;
- (b) as a result of increase in demand, the domestic industry enhanced its capacities;
- (c) even when the domestic industry was able to increase its production in proportion to increase in capacities till 2006-07, the same was not true for 2007-08. In fact, the production of the domestic industry declined whereas the capacity increased.
- (d) Capacity utilization of the domestic industry declined significantly in 2007-08.

**b) Sales volumes of domestic industry are given in the following table:-**

	Lac. Mt			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Domestic Sales	29.40	36.35	39.07	39.59
Increase in sales		6.96	2.71	0.52
Increase in demand		31.62	12.58	21.43

63. It is seen that even when demand and sales of the domestic industry for the product both were increasing over the injury period, the increase in sales in 2007-08 was marginal as compared to significant increase in demand. Thus, even when the domestic industry enhanced capacity and was having unutilized capacities and demand for the product was increasing in the market, sales volumes of the domestic industry could increase only marginally.

**c) Segment Analysis**

64. Petitioner argued that its market for the product under consideration can be grouped into a number of segments. These are Retail; Whole Sale; RMG ( Ready made Garment), Domestic; RMG Export; Export; FR/Industrial and Others. Petitioner argued that each of the above market segment represents a market with its own dynamics and while it would appear from the above overall sales volumes that the same were increasing over the injury period, sales volumes declined, if the same are examined more closely on segment basis as would be seen from the following –

	(Lac Mtrs.)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Retail	4.29	6.24	6.85	8.28
Whole Sale	5.74	9.44	9.88	9.38
RMG Domestic	10.16	12.39	11.58	11.76
RMG Export	7.35	6.80	10.62	9.06
FR	3.08	2.76	1.06	0.21
Industrial	2.71	2.71	3.07	4.34
Total Domestic	33.34	40.34	43.06	43.04
Less trading	3.94	3.98	3.99	3.45
Domestic without trading	29.40	36.35	39.07	39.59
Exports	2.59	3.84	3.40	4.06
Total sales	35.93	44.18	46.45	47.10

65. Based on the above, petitioner argued that (a) sales in the retail segment have increased significantly. This is the segment where the company has its own retail outlets. (b) sales in the wholesale segment have almost stagnated between 2005-06 and 2007-08. This is the segment where the imports are also equally present. (c) Sales in RMG domestic have in fact declined. This is the segment where the imports are directly competing with the domestic industry. (d) Sales in RMG exports have also declined in proposed POI. Imports are competing in this segment. (e) Exports of the domestic industry have been growing due to persistent efforts of the domestic industry. (f) FR is a segment where the domestic industry has almost got vanished due to dumping. (g) Industrial segment is also affected due to dumping.

66. The Authority notes that sales of the domestic industry increased only because of its own retail chain. In fact, if the sales of the domestic industry are divided into (a) retail and (b) others, it is seen that the sales of the domestic industry were stagnating/reducing, in spite of significant positive growth in the market, as would be seen from the table below.

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Retails	4.29	6.24	6.85	8.28
Other than Retails	29.05	34.10	36.21	34.76
Total	33.34	40.34	43.06	43.04

## INDEX

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Retail	100	145	160	193
Other than retail	100	117	125	120
Total Index	100	121	129	130

**d) Inventories:**

67. Inventories with the domestic industry have been as under:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Average stock	6.57	8.50	11.85	14.48
Index	100	129	180	220
Stock as no. of days of sales	75	77	102	121

The Authority notes that average stocks with the domestic industry have gone up.

**e) Profits**

68. Profits of the domestic industry declined. The domestic industry has gone into a situation of financial losses from a situation of profits upto 2006-07.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Cost of sales	Rs/Mtr	***	***	***	***
Selling Price	Rs/Mtr	***	***	***	***
Profit before tax	Rs/Mtr	***	***	***	(***)
Profit before tax	Rs/Lacs	***	***	***	(***)
PBIT	Rs/Lacs	***	***	***	***

## INDEX

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Cost of sales	Rs/Mtr	100	103	107	115
Selling price	Rs/Mtr	100	106	105	105
Profit before Tax	Rs/Mtr	100	161	81	65

69. Whereas the cost of sales increased throughout, selling price increased upto 2005-06, but declined thereafter. Consequently, profits increased in 2005-06, but declined thereafter significantly to such a situation that the domestic industry suffered financial losses in 2007-08.

70. It has been submitted that the domestic industry enhanced their capacity in the hope that it would participate in the positive growth of the product in the Country. However, unfair pricing situation created by the dumped imports prevented the company from benefiting from the increase in demand. Whereas the domestic industry made investments with the hope that it would improve its profitability, just the reverse happened due to unfair dumping of the product in the Country.

**f) Market share**

71. Share of the domestic industry and various other parties in demand in India was as under:

Figures in %

Particular	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Domestic industry	16.73	17.53	17.77	16.40
Other Indian Industry	24.58	24.26	24.87	26.05
Total Indian Industry	41.31	41.79	42.64	42.45
Subject countries	43.61	44.57	48.76	51.92
Other countries	15.08	13.64	8.61	5.63
Total imports	58.69	58.21	57.37	57.55
Total Capacity/Demand DI	100	100	100	100

72. Market share of the domestic industry improved up to 2006-07, but declined in the POI. This decline in market share is in a situation where (a) the demand in the Country showed significant growth; (b) the domestic industry had expanded capacity in order to meet higher demand. It is also relevant to point out that the price undercutting and dumping by the Chinese imports is found in the entire injury period. The market share of Indian industry remained stagnant during the Injury period. Whereas the domestic industry had hoped to improve its market share as a result of enhancement of capacities, it was faced with a situation of stagnation/reduction in market share because of dumped imports in the market.

**g) Employment and Wages**

74. Employment and wages have increased in view of additions to the capacity.

Particular	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
No. of employees	Nos.	255	262	324	328
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***
Wages per employee	Rs	***	***	***	***
Index		100	112	107	105

It is seen that wage per employee has increased over the base year.

**h) Productivity**

75. Productivity of the domestic industry shows same trend as that of production. Productivity improved in 2005-06, but declined consistently thereafter with the addition of capacities and lower utilization thereof due to dumped imports. Petitioner claimed that considering the rate of present situation and latest performance of the domestic industry, domestic industry would not be able to maintain its productivity, should the dumped imports be allowed to continue at the current prices.

Particular	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
------------	------	---------	---------	---------	---------

Production	Lac Mtrs	33.56	42.48	46.89	44.47
Productivity per day	Mtr	9589	12136	13397	12705
Productivity employee	Mtr	13161	16212	14473	13557
Index		100	112	110	103

xiii) Factors affecting domestic prices

76. Landed price of subject imports including applicable customs duty is significantly below the sales realization. Dumped imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the Indian market. Consequently, whereas cost of production continuously increased, increase in selling price in 2006-07 was lower than increase in cost of production. Further, whereas the cost of production increased, selling price declined in the POI, causing price depression and price suppression, as would be seen from the table below.

	Rs/Mtr			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Net sales realization	***	***	***	***
Landed price for subject countries	58.68	69.91	81.13	77.59
Cost of production	***	***	***	***
Price undercutting	***	***	***	***
Index	100	101	92	94

xiv) Return on investments

77. Return on investments shows the same trend as that of profits. Return on investment increased in 2005-06 with the improvement in profits, but consistently declined thereafter as a result of dumped imports in the market.

Unit		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Profit/Loss (PBIT)	Rs/Lacs	***	***	***	***
ROCE (GFA)	%	14.71	23.05	14.97	3.73
ROCE (NFA)	%	20.28	20.27	19.17	4.50
Index		100	149	95	0.22

xv) Cash Flow

78. Cash flow position of the domestic industry shows same trend as of profits. Due to pressure from subject-dumped imports, cash flow situation of the domestic industry has deteriorated, as would be seen from the table below. Though, the industry was able to make cash profits, the same were improving till 2005-06 and started declining thereafter.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Cash flow	Rs/Lacs	N A	***	***	(***)
Cash flow	Per/MTR	N A	***	***	(***)
Cash Profit	Rs/Lacs	***	***	***	***
Cash Profit	Per/MTR	***	***	***	***
Index		100	150	102	0.22

## xvi) Growth

79. The growth of the domestic industry is negative in terms of most of the parameters, more particularly after 2005-06.

**F.7.Representation from Hong Kong:**

80. We note from Annexure 1.4 that the import data on flax fabrics from Hong Kong are as follows:

Year	Volume (Mtr) (a)	Value (INR) (b)	Rate (b)/(a)	Share
2004-05	633,287	63,947,734	100.98	6.06
2005-06	986,220	89,214,724	90.46	7.80
2006-07	1,259,021	151,366,187	120.23	9.81
2007-08 (POI)	1,321,020	123,413,060	93.42	9.15

81. Article 3.2 of the WTO AD Agreement requires the Indian Authority to “consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member”. In this connection, the share of imports from Hong Kong has decreased as compared with the same period last year despite of the increase in total demand (p. 16 of the non-confidential version of petition document).

82. According to the data provided in the petition document, we have worked out the imports from Hong Kong in relation to production and consumption in India as follows:

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Import Volumes (Lac/Mtr)	6.33	9.86	12.59	13.21
Share of Imports in relation to				
Total imports in India %	6.06	7.80	9.81	9.15
Demand in India %	3.57	4.63	5.67	5.35
Indian Production %	7.97	10.33	11.92	11.83

83. The above table shows that the imports from Hong Kong have decreased relative to production or consumption in India during the POI as compared with the previous year.

Therefore, it cannot be established, or at least is inconclusive, that there has been a 'significant increase' in imports from Hong Kong in relative terms.

#### Examination by the Authority

The injury examination is carried out from the base year. From the base year, the imports from Hongkong shows an increase of approx.3%

#### CAUSAL LINK

In order to reach conclusions on the cause of the injury suffered by domestic industry and in accordance with Article 3.5 of Agreement on Anti-Dumping and Para (v) of Annexure-II of Rule 11 of the Indian Rules, the Authority examined the impact of listed factors and their consequences on the situation of the domestic industry. Known factors other than dumped imports, which could at the same time have injured the domestic industry were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.

#### General Examination of Other Known Factors

##### A. Dump and prices of imports from other sources

86. The Authority notes imports of product under consideration from other countries are either negligible or the export price is higher.

##### B. Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

86. The Authority notes that there is no contraction in the demand during POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown significant positive growth during the injury period. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which could be attributed to the injury to the domestic industry.

##### C. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

87. The Authority notes that there is a single market for the subject goods where dumped imports from subject country compete directly with the subject goods produced by domestic industry. Imports of various types of product under consideration are being sold in the same market as goods being sold by the domestic industry. No evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers has come to the notice of the Authority.

##### D. Development in technology

88. On the basis of examination of the records, the Authority provisionally holds that development in technology has not been a relevant factor for the injury to the domestic industry.



E. Export performance

89. The Authority notes that the export volumes of the domestic industry have increased over the injury period. Possible decline in exports volume does not appear to have caused injury to the domestic industry.

F. Productivity of the Domestic Industry

90. The productivity per employee has increased during the investigation period over the base year.

G. Conclusion on Causation

91. In view of the above, the Authority concludes that injury suffered by the domestic industry due to other factors is non-existent or far too insignificant as compared to injury suffered because of dumped imports ( para 47 above). The situation of the domestic industry has shown a material deterioration over the injury period, which was substantially due to dumped imports. Decline in market share of the domestic industry during investigation period as a consequence of increase in dumped import volumes leading to sub-optimal increase in sales volumes, which in turn prevented the domestic industry from improving its production & capacity utilization, price undercutting by dumped imports leading to decline in profits, return on investments and cash flow establishes that injury to the domestic industry was caused by dumped imports. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports.

H. Magnitude of Injury Margin

92. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject country and the injury margins have been worked out as follows.

## Injury margin calculations

	Rs/Mtr	
	China	Hong Kong
Landed price	74.69	105.25
NIP	***	***
Injury margin	162.59	132.03

I. Comments to Disclosure Statement

## Submissions of Domestic Industry

93. i) It has been stated that the Domestic industry has been producing and selling fabrics with below 50% flax content. During the course of investigations, the petitioner has provided detailed statement showing type-wise fabric production. It would be seen that

the petitioner has produced flax fabric having flax content below 30%. It is therefore requested to review the disclosure statement and include flax fabric with flax content of more than 30% within the scope of the product under consideration.

ii) The submissions made by Hong Kong are untenable due to various reasons.

iii) The petitioner manufactures yarn and the same is captively consumed to make fabrics. It is submitted that only captive transfer rate is required to be considered.

iv) The duty should be in terms of US\$ when the exchange rate exceeds average of the POI. The duty should be in INR when the exchange rate falls below the average of the POI.

#### 94. Examination by the Authority

The Authority notes that as per the grade-wise production statement, the domestic industry has produced fabric having flax content of 30-50%. This is 0.62% of the total production. As the domestic industry is not making substantial production of the fabric having flax content of upto 50%, the Authority has therefore concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%. The other arguments raised by the domestic industry have been duly considered in these findings.

### **G. 2. Indian industry's interest & other issues**

95. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

96. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

### **H. CONCLUSIONS:**

97. Having regard to the issues raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties including those made as comments to the disclosure statement or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. Imports originating in the subject countries are taking place at dumped prices and the same have caused material injury to the domestic industry.
- ii. Subject goods exported from the subject countries are at prices below their normal value, Non Injurious Price of the domestic industry and the net sales realization of the subject goods of the applicants, and have caused injury to the domestic industry.
- iii. Decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from the subject countries prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to growth in demand.
- iv. Significant price-undercutting and substantial increase in the volume of dumped imports adversely affected the performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow, and return on investment.
- v. Significant increase in volume of dumped imports from the subject countries (both in absolute terms as well as in relation to the share in demand) has resulted in significant decline in market share of the domestic industry.

98 Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly the Authority recommends the definitive anti dumping duty be imposed on all imports of Flax Fabrics originating in/or exported from China PR and Hong Kong. Dumping duty equal to the difference between the amount indicated in Col. 8 of the table below and the landed value of imports/kg. to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all the imports of Flax Fabrics falling under Chapter 53, Custom Sub-heading 53.09 of the Customs tariff originating in or exported from the countries mentioned below:-

Sl No	Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	53.09	Flax fabric	China	China	Any	Any	206.24	Mtr	Rs
3	53.09	-do-	China	Any	Any	Any	206.24	Mtr	Rs
4	53.09	-do-	Any	China	Any	Any	206.24	Mtr	Rs
5	53.09	-do-	Hongkong	Hongkong	Any	Any	209.72	Mtr	Rs
6	53.09	-do-	Hongkong	Any	Any	Any	209.72	Mtr	Rs
7	53.09	-do-	Any	Hongkong	Any	Any	209.72	Mtr	Rs

99. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

100. Subject to above, the Authority confirms the provisional findings dated 17<sup>th</sup> February, 2009 and corrigendum notification dated 27<sup>th</sup> February, 2009 and recommends

imposition of the anti-dumping duty as in Para above and the duty table as above from the date of imposition of provisional anti-dumping duty.

101. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

R. GOPALAN, Designated Authority